उत्तराखण्ड सरकार
सूचना ब्यूरो
(सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग)
मुख्यमंत्री आवास, न्यू कैंट रोड, देहरादून
E-mail : infodirector.uk@gmail.com
Website : www.uttarainformation.gov.in

देहरादून 17 मई, 2017(सू.ब्यूरो) प्रेस नोट–06(05/85)

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बुधवार को सचिवालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों, पुलिस अधीक्षकों एवं जनपदीय अधिकारियों के साथ प्रदेश में विकास योजनाओं तथा कानून व्यवस्था की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों को सरकार की प्राथमिकताएँ बताईं। उन्होंने कहा कि हमें गरीबी, भेदभाव, महिला उत्पीड़न एवं भ्रष्टाचार से मुक्त और समृद्धि, न्याय, पारदर्शिता, महिला सम्मान एवं स्वच्छता से युक्त राज्य बनाना है। उन्होंने कहा कि 2019 तक उत्तराखण्ड को शत–प्रतिशत साक्षर और 2021 तक सबके लिये आवास के लक्ष्य को पूरा करना है।

स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत गाँवों, सड़कों, शहरों की सफाई के साथ ही, स्वच्छता शासन–प्रशासन के कार्य कलापों में दिखायी देनी चाहिए। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरन्स हर जगह दिखना चाहिए। कार्यालयों में पारदर्शिता दिखे। आम आदमी को महसूस होना चाहिए कि सरकारी दफ्तरों में ईमानदारी से काम हो रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ईमानदारी और पारदर्शिता से सरकारी कार्यालयों में तेजी से सर्विस देना सरकार की प्राथमिकता है। स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत सप्ताह में एक दिन कार्यालय, कस्बे, ग्राम पंचायत एवं गांव में स्वच्छता अभियान पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किये जाएं। उन्होंने सभी जिलों से डम्पिंग और ट्रेंचिंग ग्राउंड के लिए प्रस्ताव भेजे जाने के निर्देश दिये।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 25 मई से राज्य स्तरीय बृहद जल संचय अभियान की शुरुआत होगी। इसके लिये मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देशित किया कि इसको वृहद कार्यक्रम के रूप में चलाया जाए। इस कार्यक्रम को घर एवं ऑफिस से शुरू किया जाए। उन्होंने कहा कि जल संरक्षण पर विशेष ध्यान दिये जाने की जरूरत है। बताया गया कि जल संस्थान एवं जल निगम द्वारा इसके लिये वृहद योजना तैयार की गई है। उन्होंने, सचिवालय और मुख्यमंत्री आवास सहित सभी सरकारी भवनों में भी रेन वाटर हॉर्वेस्टिंग व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा।

मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना को प्राथमिकता प्रदान करते हुए आम जन में व्यापक प्रचार–प्रसार करने के निर्देश दिये। मुख्यमंत्री ने कहा कि चारधाम यात्रियों के स्वास्थ्य व्यवस्था का ध्यान रखे। हृदय रोगियों को समुचित सलाह दी जाय। गुप्तकाशी में कार्डिएक एम्बुलैंस और हृदयरोग विशेषज्ञ तैनात किया जाय। चारधाम यात्रियों का रेजिस्ट्रेशन और डी–रजिस्ट्रेशन दोनो किया जाय। जो यात्री मेडिकल सलाह के विरुद्ध जाते हैं उनका भी रिकॉर्ड रखा जाय। जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग इंजीनियर्स एवं स्थानीय नागरिकों के साथ पैदल मार्ग की व्यवस्थाओं का जायजा लें। मार्ग में हो रही समस्याओं का तीव्र गति से निराकरण किया जाए। मुख्यमंत्री ने पिथौरागढ़ में लिंगानुपात को चिंताजनक बताया। उन्होंने कहा कि इसके लिये विशेष अभियान चलाया जाए। स्वास्थ्य विभाग, आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों एवं आशा वर्कर को इसमें शामिल किया जाए। सभी जिलाधिकारियों को यात्री सुविधाओं, ट्रैफिक व्यवस्था, स्थानीय दुकानदारों आदि का पूरा ध्यान रखने के निर्देश दिये। सभी हॉटलों और ढाबों में प्रशासन द्वारा निर्धारित रेट लिस्ट का प्रदर्शन सुनिश्चित किया जाय, जिससे यात्रियों को कोई असुविधा न हो।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि बुवाई के सीजन को देखते हुए किसानों को बीज और अन्य सहायता की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। किसान बीमा योजना का प्रचार प्रसार किया जाए। इसमें गैर कृषि–ऋण वाले किसान भी आच्छादित किए जाय। कृषकों को कृषक महोत्सव के माध्यम से जानकारियां उपलब्ध करायी जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि नकली बीज और खाद बेचने वालों के विरूद्ध कडी कार्यवाही की जाय।

जिलों में कानून व्यवस्था का ध्यान रखे। हरिद्वार और रूड़की में जेलों में जैमर लगाए जाएं। जेलों से अपराध संचालन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नशे के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जाएं। उन्होंने कहा कि नशे के कारोबार का राज्य से समूल नाश करना है।

मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया कि शत प्रतिशत साक्षरता का लक्ष्य निर्धारित किया जाए। इसके लिये जिलाधिकारियों की जवाबदेही फिक्स होगी। वर्ष 2019 तक प्रदेश को निरक्षरता से मुक्त करना है। निरक्षर लोगों को चिन्हित करके शिक्षण संस्थानों को इन्हें साक्षर बनाने का दायित्व सौंपा जाए।

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की प्राथमिकता वाली योजनाओं, प्र.जनधन योजना, प्र.सुरक्षा बीमा योजना, नमामि गंगे आदि को राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए सभी जिलाधिकारियों इनकी प्रगति का नियमित अनुश्रवण करने के निर्देश दिये।

इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री/शासकीय प्रवक्ता श्री मदन कौशिक, मुख्य सचिव श्री एस.रामास्वामी, डीजीपी श्री एमए गणपति, अपर मुख्य सचिव श्री डॉ.रणवीर सिंह, श्री ओमप्रकाश सहित शासन के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

देहरादून 17 मई, 2017(सू.ब्यूरो) **प्रेस नोट–05(05/84)**

विधानसभा के प्रोटोकॉल अधिकारी श्री मयंक सिंघल ने बताया कि उत्तराखण्ड विधानसभा द्वारा दिनांक 18 मई 2017 को सांय 4.00 बजे ऋषिकेश में गंगा तट, पशुलोक बैराज पर ''उत्तराखंड नदी तंत्र के संदर्भ में गंगा की निर्मलता एवं अविरलता चुनौतियां एवं समाधान'' विषय पर एक संगोष्ठी आयोजित की जा रही है, जिसमें माननीय राज्यपाल, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय मंत्रीगण, माननीय विधायकगण एवं अनेक गणमान्य महानुभाव प्रतिभाग करेंगे।

देहरादून 17 मई, 2017(सू.ब्यूरो) **प्रेस नोट–04(05/83)**

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गढ़वाली थियेटर के पुरोधा, वरिष्ठ पत्रकार और कवि श्री राजेन्द्र धस्माना के निधन पर गहरा दुःख व्यक्त किया है। उन्होंने दिवंगत की आत्मा की शांति एवं दुःख की इस घडी में शोक संतप्त परिजनों को धैर्य प्रदान करने की ईश्वर से कामना की है।

देहरादून 17 मई, 2017(सू.ब्यूरो) **प्रेस नोट–03(05/82)**

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उत्तरकाशी के खालशी मध्ये बबलूड़ा नामे तोक पर अचानक पहाड़ी से मलवा–पत्थर आने के कारण हुई दुर्घटना एवं पिथौरागढ़ में पीपली से छड़नदेव जाते समय स्थान विरकाना के समीप हुई सड़क दुर्घटना में मृतकों के प्रति गहरा दुःख व्यक्त किया है। उन्होंने दिवंगत की आत्मा की शांति एवं दुःख की इस घडी में शोक संतप्त परिजनों को धैर्य प्रदान करने की ईश्वर से कामना की है।

नितिन उपाध्याय, उपनिदेशक, सूचना : 7055007009

देहरादून 17 मई, 2017(सू.ब्यूरो) प्रेस नोट–02(05/81)

आबकारी नीति के प्रमुख बिन्दु

1. वित्तीय वर्ष 2017–18 हेतु आबकारी विभाग के लिये लक्ष्य रू.2310/–करोड़ रखा गया है।
2. वित्तीय वर्ष 2016–17 में आबकारी विभाग द्वारा रू.1905.7/–करोड़ का राजस्व अर्जन किया गया।
3. प्रत्येक जनपद में दुकानों के व्यवस्थापन हेतु जनपद के क्षमतानुसार राजस्व का लक्ष्य दिया गया है। जनपद के जिलाधिकारी उक्त राजस्व को जनपद में स्थित मदिरा की दुकानों को आवश्यकतानुसार आवंटित करेंगे।
4. वर्तमान वित्तीय वर्ष हेतु मदिरा के अतिरिक्त उठान पर पूर्ण प्रत्याभूत ड्यूटी(एमजीडी) देय होगी।
5. देशी मदिरा व विदेशी मदिरा की दुकानों हेतु आवेदन शुल्क क्रमश' रू. 22,000/– व रू. 25,000/– होगा।
6. राज्य के 04 मैदानी जनपदों को छोड़कर 09 जनपदों में देशी/विदेशी/बीयर की दुकानों के खुलने का समय 12.00 बजे से सायं 6.00 बजे तक किया जायेगा एवं मैदानी जनपदों देशी/विदेशी/बीयर की दुकानों के खुलने का समय प्रातः 10.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक किया जायेगा।
7. पात्रता की शर्तें गत वर्ष के समान होगी।
8. एम.आर.पी. में सैस 02 प्रतिशत लिया जायेगा, जिसमें से एक प्रतिशत सड़क सुरक्षा हेतु तथा एक प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा हेतु लिया जायेगा।
9. मदिरा की खरीद पर विक्रेता को कम्प्यूटर जनित रसीद देना अनिवार्य होगा तथा दुकान में स्वैप मशीन रखना भी अनिवार्य होगा।
10. ओवर रेट के प्रकरण बार–बार पाये जाने व क्रेता को कम्प्यूटर प्रिन्टेड रसीद न देने पर छठे उल्लंघन में दुकान निरस्त कर दी जायेगी।
11. जी.एम.वी.एन. व के.एम.वी.एन. को अपने गेस्ट हाउसों हेतु आवेदन करने पर बार हेतु निर्धारित अनुज्ञापन शुल्क का 50 प्रतिशत लिया जायेगा।
12. शहरी स्थानीय निकायों को छोड़कर शेष स्थानों पर देशी/विदेशी मदिरा की मिश्रित दुकानें आवश्यकतानुसार खोली जा सकती है।
13. दुकानों की स्थिति के सम्बन्ध में मा.सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 15.12.2016 एवं 31.03.2017 का अनुपालन करना बाध्यकारी होगा।

वीरेन्द्र सिंह, मीडिया प्रभारी : 7055007014

देहरादून 17 मई, 2017(सू.ब्यूरो) प्रेस नोट–01(05/80)

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की उपस्थिति में बुधवार को सचिवालय में उत्तराखंड लाइवस्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड एवं इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट के मध्य औपचारिक अनुबंध किया गया। इस अनुबंध के अनुसार इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट, आणंद के माध्यम से पशुपालन क्षेत्र का विस्तृत अध्ययन कराया जाना है।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने निर्देश दिए राज्य के 2 जिलों में (एक गढवाल एवं एक कुमांऊ) पायलट प्रोजेक्ट के रूप में पशुओं के लिए फोडर स्टोरेज विकसित किए जाएं। मुख्यमंत्री श्री रावत ने निर्देश दिए कि फील्ड सर्वे प्रशिक्षित लोगों से करवाया जाए, साथ ही ऐसे सुपरवाइजर नियुक्त किए जाएं, जिन्हें कम से कम 10 वर्ष का अनुभव हो। उन्होंने कहा कि सेक्स सीमेन का उत्पादन राज्य में ही किया जाए। इसके लिए योजना तैयार की जाए। राज्य में गौ–विज्ञान एवं गौ–मूत्र केंद्र विकसित किये जाएं। स्थानीय नस्लों के सीमेन बैंक बनाए जाएं। उन्होंने शुद्ध भारतीय नस्लों हेतू बैंक बनाए जाने पर बल दिया। मुख्यमंत्री श्री रावत ने स्थानीय बद्री गाय पर विशेष अध्ययन करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्थानीय गायों से हमें किस प्रकार अधिक मुनाफा मिल सकता है इसका अध्ययन कराया जाए। मुख्यमंत्री श्री रावत ने कॉन्पैक्ट फीड ब्लॉक बैंक बनाए जाने पर बल दिया। इसके लिए उन्होंने राज्य की आवश्यकता का आंकलन करने के निर्देश दिये। मुख्यमंत्री श्री रावत ने उन्नत नस्ल के पशुओं का प्रयोग किए जाने को प्रोत्साहित करने के लिए एवं दुग्ध संघों को प्रोत्साहित किया जाने पर बल देते हुए कहा कि राज्य में चीज (cheese) के उत्पादन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के समक्ष अनुबंध में उत्तराखंड लाइव स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड की ओर से सचिव श्री आर मीनाक्षी सुंदरम व इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट, आणंद के निदेशक डॉ. राकेश सक्सेना ने हस्ताक्षर किये।

इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव डॉ. रणवीर सिंह, सचिव श्री आर. मीनाक्षी सुंदरम सहित संबंधित विभागों के उच्चाधिकारी उपस्थित थे।

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।